

आजम खान समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर खबर पर पैनी नज़र

o"Kz %13 vdl %07

y[kuA] 'kfuokj 21 ebl 2022 l s 27 ebl 2022 rd

i"B&8

eW; %, d : i ; k

कारोना के बाद मंकीपॉक्स ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, हवाईअड्डे और बंदरगाह के अधिकारियों को दिया निर्देश

नयी दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के बाद एक और वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और आईसीएमआर को स्थिति

है कि मंकीपॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा की हिस्ट्री वाले किसी भी बीमार यात्री को अलग कर दिया जाए और नमूने जांच के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोल जी की बीएसएल4

वृद्धि के बीच उसने चेचक के ऐसे टीकों की खरीद की कवायद तेज कर दी है जोकि इस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम कर सके। मंकीपॉक्स भी चेचक जैसा ही संक्रमण है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इंग्लैंड में मंकीपॉक्स के 99 और मामले पाए गए हैं, जिसके बाद देश में इस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 20 तक पहुंच गई है। मंकीपॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। यह पहली बार 1965 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। मंकीपॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1960 में दर्ज किया गया था। यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्ण-कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है और कभी-कभी अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाता है। मंकीपॉक्स का संक्रमण बेहद करीबी संपर्क वाले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल कपड़े या चादरों का उपयोग करने से संक्रमण फैल सकता है जोकि मंकीपॉक्स की चपेट में है।



पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। दरअसल, यूके समेत कई देशों में मंकीपॉक्स के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने हवाईअड्डे और बंदरगाह के अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाईअड्डे और बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है। सूत्र ने बताया कि उन्हें निर्देश दिया गया

सुविधा को भेजे जाएं। सूत्र ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और आईसीएमआर को स्थिति पर कड़ी नजर रखने और निगरानी करने का निर्देश दिया। यूके, यूएसए, पुर्तगाल, स्पेन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों से मंकीपॉक्स के मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत में अभी तक इससे संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि मंकीपॉक्स के मामलों की संख्या में

27 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान ने कहा मेरी तबाहियों में मेरे अपने लोगों का बड़ा योगदान

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव समेत भारी मात्रा में समर्थकों ने उन्हें रिसीव किया। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ट्वीट कर उनका स्वागत किया। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में सपा नेता आजम खान ने कहा कि हाई कोर्ट के कुछ फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से शत प्रतिशत मामलों में जिस तरह हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो शक्ति उसको मिली थी उसका सही और जायज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि

अभी मेरे लिए भाजपा, बसपा और कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि मुझ पर, मेरे परिवार और मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमों दायर किए हैं उसमें मैं कहूंगा कि मेरी



तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा योगदान है। मालिक उन्हें सदबुद्धि दे। दरअसल, आजम खान के इस बयान को सपा पर जवाबी हमला माना जा रहा है और उनके परिवार ने तो पहले ही उपेक्षा का आरोप भी लगाया था।

अखिलेश यादव ने आजम खान के रिहा होने पर ट्वीट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता तथा विधायक आजम खान के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं। पूरा ऐतबार है कि वे अन्य सभी झूठे मामलों-मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं! आपको बता दें कि आजम खान पिछले 27 महीनों से जेल में बंद थे। हालांकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को पहले ही जमानत मिल गई थी लेकिन आजम खान को जमानत नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई।

अब सदन में मोटा बैग लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 92वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण, प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन 20 और 29 मई को किया गया है। राज्य की 92वीं विधानसभा में निर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम (प्रशिक्षण कार्यक्रम)का उद्घाटन 20 मई, को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधायकों के ई-विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। ई-विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा शायद देश की सबसे बड़ी विधानसभा होगी, ये प्रदेश वो प्रदेश है जहां के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सदन

में आपको बहुत मोटा बैग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधायक जब सदन में आते थे तो अपने साथ सहायक को साथ लेकर चलते थे। बहुत बार उनकी सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस होती



थी कि उनका सहायक बैग लेकर सदन तक उनके साथ जाए। अब ई-विधान के बाद आपका काम सरल हो जाएगा। 29 मई को सुबह 9:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का समापन करेंगी। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी भी विधायकों को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की 803 सदस्यीय विधानसभा का निर्वाचन मार्च में संपन्न हुआ। विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार कुल 803 सदस्यों वाली विधानसभा में 92 सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर आये हैं।

चिकित्सक हड़ताल का न लें सहारा : दिल्ली हाई कोर्ट

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चिकित्सकों को हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे उनकी सेवाएं प्रभावित होती हैं और उसके गंभीर परिणाम होते हैं। इससे मरीजों की जान को भी खतरा हो सकता है। न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सकों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा, "मरीज को कुछ भी हो जाए तो यहां चिकित्सकों को पीटा जाता है, हमारे यहां यह स्थिति है।" उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हड़ताल में शामिल चिकित्सकों के खिलाफ

उपयुक्त कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चिकित्सकों या जनता की सेवा करने वाले किसी अन्य पेशे से



संबंधित व्यक्तियों द्वारा हड़ताल का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की हड़ताल से सेवाओं पर गंभीर असर पड़ता है। पीठ ने कहा, "चिकित्सकों के मामले में इस तरह की हड़ताल का असर और गंभीर होगा क्योंकि इससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है।"

सम्पादकीय

यथार्थ को स्वीकार करने का साहस

कांग्रेस ने उदयपुर में अपने चिंतन शिविर में अपने और देश के वर्तमान यथार्थ को स्वीकार करने का साहस दिखाया— यह कहा जा सकता है। इसके अनुरूप उसने अपनी रणनीति और कार्यनीति को ढालने का फैसला किया है— यह भी वहां स्वीकार किए गए नव संकल्प घोषणा पत्र से स्पष्ट है। असल में क्या होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ बातों ने ध्यान खींचा। मसलन, राहुल गांधी का यह स्वीकार करना कि कांग्रेस का जनता का जनता से संवाद और संपर्क टूट गया है। उनकी दूसरी यह बात महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सत्ता के सभी केंद्रों पर अपनी पकड़ बना ली है, अब उसके खिलाफ संघर्ष में कोई शर्ट कट नहीं है। दरअसल, संघर्ष की बात कहना ही अपने-आप में अहम है। इससे बात चुनावी रणनीति और जोड़-तोड़ से आगे जाती है। यह समझ भी सही दिशा में है कि अब कांग्रेस के नेता हों या कार्यकर्ता— सबको जनता के बीच सचमुच जाना होगा— यानी सिर्फ जनता के पास जाने की रस्म-अदायगी से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने राजनीतिक-आर्थिक- सामाजिक संदेशों का भी नव-आविष्कार करने की कोशिश की है। मसलन, अर्थव्यवस्था के संबंध में उसका फिर से सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका पर जोर देना, आर्थिक नीति में रोजगार को केंद्रीय महत्त्व देना, किसानों की स्वामीनाथन फ मूले के मुताबिक न्यूनतम मूल्य की मांग का समर्थन करना, और नए सामाजिक यथार्थ के मुताबिक सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात को स्वीकार करना— एक नव चिंतन की तरह है। अगर ये चिंतन सचमुच कांग्रेस नेतृत्व, संगठन और कार्यकर्ताओं के मानस में उतर पाया, तो कहा जा सकता है कि हाल की चुनावी हार से लगे झटके सार्थक हुए हैं। अगर इस चिंतन से कांग्रेस इस भ्रम से निकल पाई कि वह भारत में शासन की कुदरती पार्टी है और अपने को प्रबंधकीय भूमिका से निकाल कर फिर राजनीतिक संगठन बना पाई, तो उसके पुनरुद्धार की जमीन तैयार हो सकती है। देश को उससे ऐसी समझ और पहल की आशा है, यह एक जग-जाहिर बात है। इसलिए उसके नए संकल्प पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।

स्वतंत्र देव सिंह को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी, बने विधान परिषद के नेता सदन

लखनऊ। योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। स्वतंत्र देव सिंह को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता सदन बनाए गया

सिंह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के दौरान परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि जब उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे



है। वह पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की जगह लेंगे। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक हैं जिन्हें संगठन के साथ-साथ सरकार में भी काम करने का लंबा अनुभव है। स्वतंत्र देव सिंह को योगी आदित्यनाथ का बेहद विश्वसनीय बताया जाता है। यही कारण है कि उन्हें विधान परिषद में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी भाजपा को बहुमत है। २३ मई से शुरू होने वाले विधान मंडल के बजट सत्र में स्वतंत्र देव सिंह की भूमिका अहम रहेगी। स्वतंत्र देव

दिया था। स्वतंत्र देव सिंह का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। लेकिन उनका कार्यक्षेत्र बुंदेलखंड ही रहा है। उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। बावजूद इसके स्वतंत्र देव सिंह ने राजनीति में अहम मुकाम हासिल किए हैं। उन्हें आरएसएस का भी बेहद करीबी माना जाता है। स्वतंत्र देव सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही भाजपा ने २०२२ का विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीत जीता है। स्वतंत्र देव सिंह को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी विश्वसनीय माना जाता है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के दो हजार बच्चों को लैपटाप देगी योगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के दो हजार बच्चों को लैपटाप प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इन बच्चों को छह माह में लैपटाप प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस पर करीब आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निराश्रित हुए बच्चों के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जून २०२१ में शुरू की थी। सरकार इन बच्चों के पालन पोषण से लेकर इनकी पढ़ाई तक का खर्च उठाती है। ऐसे बच्चों को चार हजार रुपये प्रति माह सरकार देती है। इस योजना के तहत करीब दो हजार विद्यालय जाने वाले बच्चों को सरकार लैपटाप प्रदान करेगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब तक ११,०४६

पात्र बच्चों का चयन हुआ है। इन्हें प्रत्येक तीन माह पर १२-१२ हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इनमें से ४८० बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता दोनों की ही मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी। शेष



१०,५६६ ऐसे बच्चे हैं जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है। प्रदेश सरकार विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करवा रही है। इनमें से दो हजार बच्चों को सरकार आगामी छह माह के अंदर लैपटाप प्रदान करेगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक सुरक्षा

सेक्टर की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिया था कि कोरोना संक्रमण से अपने अभिभावकों को खो चुके निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटाप दिया जाए। योजना के तहत पंजी त ६वीं या इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। २००० पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल देखरेख संस्थाओं किशोर न्याय बोर्डों एवं बाल कल्याण समितियों का एमआईएस पोर्टल जल्द होना चाहिए। इसे अगले १०० दिन में करने का लक्ष्य रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना और बाल सेवा योजना योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए ब्लक स्तर पर कैंप आयोजित करें।

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला जिला जज को किया ट्रांसफर, कहा- वे न्यायिक अधिकारी होते हैं, हम नहीं दे सकते निर्देश

लखनऊ। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई दोपहर तीन बजे से शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। ज्ञानवापी पर फैसला जिला को लेना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीन बड़े सुझाव सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए। पुलिस प्रशासन को देखना होगा कि कितनी संख्या में वहां पर जा सकते हैं। तीसरी बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है कि मामला कम्प्लैक्स है वाराणसी में ही कोर्ट में ही मामला सुना जाए। कोर्ट ने कहा है कि आठ हफ्ते तक उनकी तरफ से जारी किया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया है कि जो जिला जज न्यायिक अधिकारी होते हैं। जिला जज को हम निर्देश नहीं दे सकते हैं। कमीशन की रिपोर्ट को कैसे

डील करना है। अदालतें को उसी मामले की सुनवाई करनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें। हिंदू पक्षकारों की तरफ से २७८ पन्नों का विस्तृत हलफनामा दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी का मामला उपासना स्थल कानून १९६१ के दायरे में नहीं आता है क्योंकि ये १५ अगस्त १९४७ को किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को लेकर है। जबकि ज्ञानवापी परिसर में स्थित देवी श्रृंगार गौरी की उपासना, पूजा और दर्शन पिछली सदी के आखिरी दशक तक हो रही थी। अदालत पहले धार्मिक स्थलों की स्थिति के सवालों पर पहले सुनवाई करे। फिर उसके कैरेक्टर और स्थिति की समीक्षा हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई छह जुलाई तक के लिए टाल दी। वाराणसी के अंजुमन इतेजामिया मस्जिद और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया ने सुनवाई की अगली तारीख छह जुलाई तय

की। उल्लेखनीय है कि मूल वाद वर्ष १९६१ में वाराणसी की जिला अदालत में दायर किया गया था, जिसमें वाराणसी में जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, वहां प्राचीन मंदिर बहाल करने की मांग की गई थी। वाराणसी की अदालत ने आठ अप्रैल, २०२१ को पांच सदस्यीय समिति गठित कर सदियों पुरानी



ज्ञानवापी मस्जिद का समग्र भौतिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने आठ अप्रैल के इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह कहते हुए चुनौती दी कि वाराणसी की अदालत का यह आदेश अवैध और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। याचिका में कहा गया कि वाराणसी की अदालत में यह विवाद सुनवाई योग्य है या नहीं, यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

घर से भटकी १८ वर्षीय युवती को पुलिस ने मिलाया परिजनों से

लखनऊ। आशियाना कोतवाली प्रभारी दीपक पांडेय ने बताया कि थाना क्षेत्र के बंगला बाजार चौकी प्रभारी लव शुक्ला गुरुवार शाम अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गस्त के दौरान बंगला पुल पर एक युवती परेशान दिखी। उससे पूछताछ की गई तो वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान लग रही थी। महिला आरक्षियों ने तो युवती ने अपना परिचय दिया। पुलिस के मुताबिक

युवती ने अपना परिचय नेहा (१८) निवासी कानपुर नगर के बिल्हौर



थाना अंतर्गत आने वाले मनकपुर निवासी नूर आलम की बेटी के

रूप में दिया है। युवती मानसिक रूप से परेशान थी इसके चलते भटकते हुए राजधानी लखनऊ आ पहुंची थी। इसके बाद कानपुर पुलिस की मदद से परिजनों को सूचना दी गई और युवती का मेडिकल परिक्षण करवाया गया। वहीं सूचना पाकर लखनऊ पहुंचे परिजनों ने अपनी बेटी को सकुशल पाकर पुलिस की काफी सराहना किये।

'बुलडोजर बाबा की सरकार' ने ५० दिनों में ५९४ करोड़ की संपत्ति कराई मुक्त

लखनऊ। योगी सरकार २.० ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शुरुआत से ही अपना रुख साथ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली 'बुलडोजर बाबा की सरकार' ने प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। ५० दिनों में चिह्नित ५० माफिया एवं उनके गैंग के सदस्यों के कब्जे से ५९४ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मुक्त कराई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर और सख्ती का संदेश देने के लिए कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है। इसी तरह वन, खनन, शराब, पशु तस्करी व भूमि पर अवैध कब्जे के धंधे में लिप्त माफिया को चिह्नित कर गैंगस्टर एक्ट की धारा १४(१) के तहत अब तक ५१३ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अभी अभियान को और तेज करने की तैयारी है। प्रदेश के ५० सबसे बड़े माफिया पर पूरी तरह नकेल कसने का प्लान तैयार किया गया है। पिछले दिनों सीएम योगी

आदित्यनाथ को यूपी पुलिस ने जो प्लान पेश किया था उसके मुताबिक अगले दो साल में इन माफिया की १२०० करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। माना जा रहा है कि अगले लोकसभा



चुनाव से पहले सरकार अपराध के खिलाफ सख्ती को लेकर अपनी छवि और मजबूत करना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी पुलिस के आला अधिकाारियों ने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें १०० दिनों के भीतर २५ माफिया के बजाय ५० प्रमुख माफिया के खिलाफ कार्रवाई की सप्तावार समीक्षा की जाएगी और कोर्ट में लंबित केसों में अगले १०० दिन में दोष सिद्ध कराया जाएगा। खनन, शराब, पशु, वन, भू-माफिया को चिह्नित करके धारा १४ (१)

गैंगस्टर एक्ट के तहत ५०० करोड़ रुपये की जब्तीकरण का लक्ष्य रखा गया है। टाप १० अपराधियों को चिह्नित करके पूरे प्रदेश में लगभग १५ हजार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने छह महीने में गैंगस्टर एक्ट के तहत ८०० करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा है। सभी जिलों में शाम के समय बाजारों और भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस की फुट पैट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के १० जिलों में हाइटेक ला एंड आर्डर क्यूआरटी टीम स्थापित की जाएगी। आतंकवाद निरोधक बल (एटीएस) ने कहा है कि अगले १०० दिनों में देश विरोधी गतिविधियों जैसे अवैध धर्मांतरण, आतंकवाद, नक्सलवाद, अवैध शस्त्र तस्करी, टेरर फंडिंग, आइएसआइ पाक अजेंट, स्लीपर सेल्स, ऑनलाइन रेडिक्लाइजेशन, अवैध अप्रवासी रोहिंग्या/बांग्लादेशियों व अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

यूपी विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल करेंगे प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अठारहवीं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सदन की कार्यवाही, नियमों और परंपराओं के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को विधानसभा मंडप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि इसका शुभारंभ करेंगे, जबकि शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उद्बोधन होगा। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विपक्ष के दिग्गज और पूर्व जनप्रतिनिधि भी विधायकों को सदन की कार्यवाही, संसदीय परंपराओं आदि का पाठ पढ़ाएंगे। विधायकों को ई-विधान का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन विधानसभा मंडप में लोकसभा अध्यक्ष सुबह १०:४५ बजे बजे पहुंचेंगे। स्वागत उद्बोधन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के संबोधन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ई-विधान का उद्घाटन कर विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना के आभार जताने के साथ उद्घाटन सत्र का समापन होगा। दोपहर दो बजे से नवीन भवन स्थित तिलक हाल में विधायकों का

प्रबोधन कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें सुरेश खन्ना सदस्यों को संसदीय शिष्टाचार एवं आचरण का पाठ पढ़ाएंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी कार्य स्थगन, अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न एवं शून्य प्रहर विषय पर प्रशिक्षण देंगे। औचित्य का प्रश्न



और संसदीय समितियां विषय के वक्ता पूर्व मंत्री डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी होंगे, जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित संसदीय प्रश्न और प्रश्न पूछने का तरीका नए विधायकों को बताएंगे। दूसरे दिन का सत्र शनिवार सुबह ११ बजे तिलक हाल में शुरू होगा, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अपने विचार रखेंगे। दोपहर दो बजे विधान सभा मंडप में ई-विधान का प्रशिक्षण शुरू होगा। सबसे पहले विषय की जानकारी महाना देंगे। इसके बाद एनआइसी के विशेषज्ञ विधायकों को तकनीकी जानकारियां देंगे। शाम ४:३० बजे दो दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा।

लेनदेन को लेकर नाराज दुल्हन ने कर ली आत्महत्या

लखनऊ। पसंद की बाइक न मिलने से नाराज दूल्हे ने जयमाल के बाद शादी से इनकार कर दिया और मंडप से वापस लौट गया। इससे नाराज दुल्हन ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दो दिन पहले तक गांव में शादी की तैयारियों को लेकर हर तरफ खुशनुमा माहौल था। वहीं, दुल्हन की आत्महत्या से अब मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी की जुबान पर तरह-तरह की चर्चा है। ग्रामीणों ने बताया कि माल के नरायणापुर गहदो निवासी अमित की बेटी संध्या की शादी थी। संध्या की शादी नौबस्ता सलेहनगर निवासी ठाकुरदीन के बेटे अमर बहादुर से हो रही थी। शादी में कोई कमी न रहे, इसका पूरा ख्याल रखा गया। दहेज के लिए दूल्हे की हर मांग पूरी की गई। आर्थिक

स्थिति ठीक न होने के कारण मांगी गई अपाचे बाइक की जगह स्प्लेंडर खरीदी गई थी। रविवार १५ मई को बरात दरवाजे पहुंची। धूमधाम से बरात का स्वागत किया गया। दूल्हा व उसके दोस्त नाचते-गाते स्टेज पर पहुंचे। वहां जयमाल संपन्न हुआ। इसके बाद दूल्हे की नजर स्टेज से उतरते ही दहेज में मिली बाइक पर पड़ गई तो वह भड़क गया। उसने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष के लोग मान-मनौबल में जुट गए, लेकिन दूल्हा अचानक उठा और अपने रिश्तेदारों के साथ मंडप से निकल गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि लड़के वालों की तरफ से जेवर कम आने की वजह से लड़की के घरवालों ने उन्हें काफी भला-बुरा कहा था। इसी से नाराज होकर बारात वापस हो गई थी। दूल्हा जहां बाइक के लिए हंगामा

कर रहा था। वहीं जैसे ही मंडप में कार्यक्रम शुरू हुआ तो घर की महिलाओं ने जेवरात देख नाराजगी जाहिर की। इस बात पर दोनों पक्षों में काफी देर तक कहासुनी चलती रही। इस पर नाराज दूल्हा और उसके करीबी रिश्तेदार वहां से चले गए। दूल्हा पक्ष दुल्हन को जेवरात नहीं देना चाहता था। आरोप है कि बाइक तो सिर्फ बहाना था। घटना से सदमे में आई दुल्हन संध्या ने सोमवार की रात घर में ही फांसी लगा ली थी। घरवालों ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या किए जाने की बात कही है। थानाध्यक्ष माल रविन्द्र कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। सही तथ्यों की खोजबीन की जा रही है। संध्या की मां शांति ने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। हमें किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना।

एमएससी छात्र के साथ हुई मारपीट के मामले में अभिषेक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

लखनऊ। आशियाना थाना क्षेत्र के बीबीएयू में रैगिंग को लेकर दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रविवार को हुई मारपीट के मामले में जहां एमएससी के छात्र ने बीटेक के छात्र व उसके १५ अज्ञात साथियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत बलवा, मारपीट जैसी तमाम धाराओं में मुकदमा लिखवाया था वहीं बुधवार शाम बीटेक के छात्र ने भी क्रास एफआईआर करवाया है। उसने एमएससी के छात्र व उसके ५ साथियों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखवाया है। फिलहाल दोनों पक्ष के मामले दर्ज करके आशियाना पुलिस जांच में जुटी है। आशियाना कोतवाली प्रभारी दीपक पांडेय ने बताया कि बीबीयू के एमएससी के छात्र अभिषेक की तहरीर पर बीटेक के छात्र शिवम

शर्मा और उसके १५ अज्ञात साथियों के खिलाफ एससी एसटी के तहत मुकदमा लिखा गया था वहीं बुधवार को दूसरे पक्ष शिवम शर्मा ने भी क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाया है। शिवम ने आरोप लगाया है कि शनिवार को उसका अरविंद कात्वा के साथ मामूली विवाद हुआ था जिसको लेकर अरविंद के दोस्त अभिषेक ने बदला लेने की बात कही थी। रविवार रात जब कैम्पस के अंदर ही शिवम अकेले आता दिखा तो अभिषेक ने अपने साथियों अरविंद, धीरज कनौजिया, बसंत कनौजिया, गौरव वर्मा, और इशियाक अहमद के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा साथ ही एससी एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी। दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच किया जा रहा है।

डीजीपी डीएस चौहान की बड़ी कार्रवाई, उन्नाव में

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक देवेन्द्र सिंह चौहान को पुलिसकर्मियों के साथ जरा सी भी अभद्रता बर्दाश्त नहीं है। उन्नाव तथा बिजनौर में मंगलवार को पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता के मामले में उन्होंने उन्नाव और बिजनौर के पुलिस अधीक्षक को तत्काल ही एक्शन लेने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं दोषियों के

खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करने को कहा। डीजीपी देवेन्द्र सिंह चौहान के इस अल्टीमेटम के बाद उन्नाव और बिजनौर का पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया। उन्नाव और बिजनौर में पुलिसकर्मियों से अभद्रता के मामले में डीजीपी के आदेश के बाद सख्त कार्रवाई की गई। उन्नाव में तीन व्यक्तियों और बिजनौर में एक अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया। डीजीपी चौहान ने कहा कि प्रदेश में पूर्ण निष्ठा एवम् ईमानदारी से काम करने वाले पुलिसकर्मियों के मान सम्मान की रक्षा प्रत्येक दशा में किसी भी कीमत पर की जाएगी। वर्दी की इज्जत से खेलने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वर्दी पहनने वालों से अभद्रता करने वाला कोई भी कहीं पर भी नहीं

तीन व बिजनौर में एक गिरफ्तार

छोड़ा जाएगा। डीजीपी ने सभी जिला पुलिस प्रशासन को इस बाबत निर्देश दिया है कि किसी भी वर्दी वाले के साथ अभद्रता की जानकारी मिलने पर तत्काल एक्शन लें। इतना ही नहीं सभी जगह पर गलत काम करनेवाले पुलिस कर्मियों को सजा और कर्तव्यनिष्ठों का सम्मान बचाना जरूरी है। प्रदेश के सभी पुलिस

कर्मियों के सम्मान की रक्षा की जाएगी। उनके मान सम्मान की रक्षा प्रत्येक दशा में की जाएगी। इसी क्रम में उन्नाव और बिजनौर में पुलिसकर्मियों से अभद्रता मामले में कार्रवाई की गई है। उन्नाव में ट्रैफिक पुलिस कर्मी से अभद्रता की गई तो बिजनौर में चेकिंग करने वाली टीम के साथ मारपीट की गई।

हिन्दी विवाद के बीच बोले मोदी-भारतीय भाषाओं को भारतीयता की आत्मा मानती है भाजपा

नयी दिल्ली। आज से राजस्थान में शुरू हुए भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भाषा को लेकर हो रहे विवाद पर अपनी टिप्पणी की। बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि भाषाओं के आधार पर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा हर क्षेत्रीय भाषा में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब देखती है और उन्हें पूजा के योग्य मानती है। हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हर क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देना, हर क्षेत्रीय भाषा के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। भाजपा, भारतीय भाषाओं को भारतीयता की आत्मा मानती है

और राष्ट्र के बेहतर भविष्य की कड़ी मानती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर भी जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश



का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई-भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि मैं आज के युवाओं की भाषा में कहूँ तो जो भारत के समृद्ध भविष्य के बवकम लिखने के लिए लालायित हैं, ऐसे हर युवा को हमें भाजपा के साथ

जोड़ना है। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आज कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों को भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। उन्होंने कहा कि जिस एक और विषय पर हमें निरंतर काम करते रहना है वो है देश में विकासवाद की राजनीति की चौतरफा, चारो दिशा में स्थापना होनी चाहिए। कोई भी दल हो, उसको भी विकासवाद की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करना है। मोदी ने कहा कि मैं सैचुरेशन की बात करता हूँ। सैचुरेशन सिर्फ पूर्णता का आकड़ भर नहीं है। ये भेदभाव, भाई-भतीजावाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है।

सहारनपुर में छेड़खानी को लेकर दो समुदाय के लोगों में झड़प, दो घायल

सहारनपुर (उप्र)। जिले के देवबंद थाना क्षेत्र में युवती से कथित छेड़खानी की घटना के बाद दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प में दो व्यक्ति घायल हो गए। एक हिंदू संगठन की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें से चार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात एक युवक ने युवती से कथित तौर पर छेड़छाड़ की जिसके बाद बाजार के लोग महिला के समर्थन में उतर आए। इस बीच युवक ने एक व्यापारी पर छड़ से

हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि कुछ ही देर में अलग-अलग समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए और लाठियों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों का एक-एक व्यक्ति घायल हो गया। इस घटना के विरोध में भाजपा नेता और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग रात में ही धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सूरज राय ने बताया कि बीती रात एक युवती बाजार से लौट रही थी कि तभी एक

शातिर युवक ने उसके साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की। इसके बाद कई दुकानदार युवती के समर्थन में आगे आ गये। राय ने बताया कि इसके बाद युवक ने एक व्यापारी पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। राय ने बताया कि एक हिंदू संगठन की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें से चार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।

फिर शुरू किसान आंदोलन

नयी दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अब अहसास हुआ होगा कि सत्ता में ना रहने पर समाज के किसी भी वर्ग के असंतोष और आंदोलन का समर्थन करना कितना आसान होता है। उधर पंजाब के किसानों को भी यह अहसास हो रहा है कि कोई पार्टी सिर्फ नाम रख लेने भर से आम आदमी की समर्थक नहीं हो जाती। इन अहसासों का कारण पंजाब खड़ा हुआ ताजा टकराव है। पंजाब के सैकड़ों किसान अब राज्य के बाहरी इलाके चंडीगढ़ बॉर्डर पर जुट गए हैं। उनका ये जुटाव उसी तर्ज पर है, जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर किया था। इस बार उनकी एक मांग गर्मी के कारण गेहूँ की फसल की बर्बादी झेलने वाले किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल का मुआवजा देने की है। उनकी अन्य

प्रमुख मांगों में मक्का, बासमती और मूंग की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा शामिल है, जिसका चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने वादा किया था। किसानों को इस बात पर भी आपत्ति



है कि राज्य सरकार ने अचानक 9 जून से धान की रोपाई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया। मंगलवार को किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और चंडीगढ़ की ओर जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जिसके बाद किसान चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर

ही धरना देकर बैठ गए। इसके पहले पिछले हफ्ते पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह के साथ किसान यूनियन की बातचीत विफल हो गई थी। उसके बाद यूनियन नेताओं ने धरने की घोषणा की थी। धरने पर बैठे किसान अपने साथ राशन, गैस सिलेंडर, खाना पकाने का सामान, बिस्तर और कूलर लेकर आए हैं। जाहिर है, उनका इरादा लंबे समय तक डेरा डालने का है। किसानों को संभवतः यह महसूस हुआ है कि उनके पास अपनी मांगें मनवाने का एक कारगर मॉडल है। एक समय आम आदमी पार्टी ने इस मॉडल का समर्थन किया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि किसानों का आंदोलन गैर-जरूरी है। अब अगर किसान इसे वादाखिलाफी मान रहे हों, तो इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पेगासस स्पाइवेयर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए दिया 20 जून तक का समय

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पेगासस विवाद पर विचार करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त तकनीकी और पर्यवेक्षी समितियों द्वारा रिपोर्ट जमा करने का समय बढ़ाते हुए कहा कि ये चार सप्ताह में पूरी हो जानी चाहिए। इजराइली स्पाइवेयर को लेकर 26 'प्रभावित' मोबाइल फोन की जांच की जा रही है और इस प्रक्रिया को चार हफ्ते में पूरा हो जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिपोर्ट तब पूर्व एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन को सौंपी जाएगी जो अभ्यास की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें अपनी टिप्पणी जोड़ने में 95 दिन और लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाइवेयर की जांच पर कहा कि 'प्रभावित उपकरणों' की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि 26 मोबाइल उपकरणों की जांच की जा रही है। उन्होंने अपना खुद का सॉफ्टवेयर विकसित किया है। उन्होंने सरकार और पत्रकारों सहित एजेंसियों को नोटिस भी जारी किए हैं और आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं। इनकी तरफ से अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए समय की प्रार्थना की है अब यह

प्रक्रिया में है। हम उन्हें समय देंगे। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने समिति से मोबाइल उपकरणों की जांच में तेजी लाने को कहा, अधिमानतः चार सप्ताह में और अपनी रिपोर्ट निगरानी न्यायाधीश को भेजने को कहा। समय के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने बताया



कि वह मामले की अगली सुनवाई जुलाई में करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालांकि इसका विरोध करते हुए कहा कि यह केवल एक अंतरिम रिपोर्ट है। कोर्ट ने ने अक्टूबर 2021 में इजरायली स्पाइवेयर के कथित उपयोग की जांच के आदेश दिए थे। एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने दावा किया था कि पेगासस स्पाइवेयर के जरिये कथित निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर शामिल थे।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बोले असदुद्दीन ओवैसी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है स्थानीय डीएम

हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। उन्होंने



कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति दी जाए, जिसमें तालाब से वजू करना शामिल है क्योंकि कोई भी जब तक वजू न करे तब तक नमाज नहीं पढ़ सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से लागू करे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय डीएम याचिकाकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति

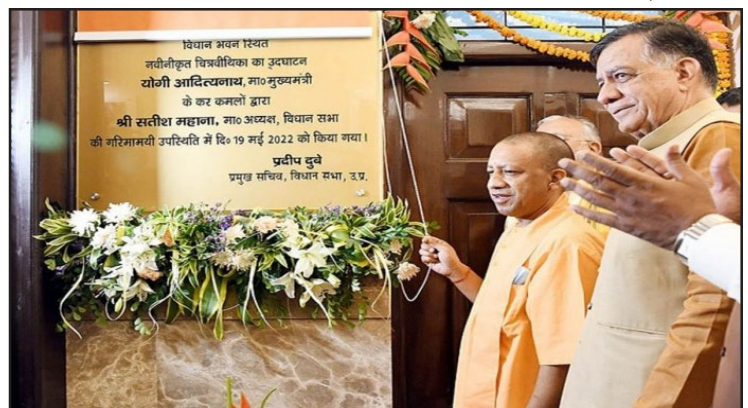
दे, तो इसमें तालाब से वजू शामिल है। जब तक वजू न करे तब तक नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फव्वारा संरक्षित किया जा सकता है लेकिन तालाब खुला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य के विवादों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1989 बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह कानून संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत को इस बात पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दायर दिवानी वाद की सुनवाई वाराणसी के दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के पास से जिला न्यायाधीश (वाराणसी) को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए बेहतर होगा कि एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी इसे देखे। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह की पीठ ने कहा कि वह दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) पर कोई आक्षेप नहीं लगा रही है, जो पहले से मुकदमे पर सुनवाई कर रहे थे।

सीएम योगी ने किया ई-विधान केन्द्र का लोकार्पण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विकास कार्य के तहत पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने अधिकांश सरकारी कार्यालय को

आनलाइन संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्यवाही को कागज रहित बनाने के लिए विधानमंडल के बजट सत्र से नेशनल ई-विधान

मौर्य तथा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी थे। अब उत्तर प्रदेश में ई विधान मंडल सत्र होगा। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र इस बार पूरी तरह से पेपरलेस होगा। सभी विधायकों की सीट पर टैबलेट लगवा दिया गया है। अब उनके सवाल से लेकर जवाब तक सब डिजिटल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने इसके बाद विधानभवन की गैलरी में हुए सुंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। सौन्दर्यीकरण के तहत विधान भवन की गैलरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, वीरगंगा लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पाण्डेय, सरदार भगत सिंह तथा टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाई गई हैं।



पेपरलेस करने का कदम उठाने के साथ अब उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्यवाही को भी पेपरलेस कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गुरुवार को ई-विधान एप्लीकेशन केन्द्र का लोकार्पण किया, जिससे विधानसभा की कार्यवाही का

परियोजना को लागू करने की तैयारी को सरकार ने पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान भवन में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन केन्द्र का लोकार्पण किया। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद

अवैध देशी तमंचा व दो जिन्दा कारतूस संग शातिर गिरफ्तार



महेन्द्र कुमार पुत्र बेचा लाल निवासी ग्राम सराय अलीपुर थाना काकोरी लखनऊ के रूप में दिया है। पकड़े गए शातिर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।

लखनऊ। आशियाना पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर एक शातिर को अवैध ३१५ वोर का देशी तमंचा व दो जिन्दा कारतूस संग गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। आशियाना थाना प्रभारी दीपक पाण्डेय ने बताया कि गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र स्थित एम एन पुलिया रेलवे क्रासिंग के पास से एक शातिर को एक ३१५ वोर का तमंचा व दो जिन्दा कारतूस संग गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार में आए शातिर ने पुलिस पूछताछ में अपना परिचय

पीजीआई निदेशक की रिसेप्शन अधिकारी के घर चोरी

लखनऊ। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, के निदेशक की रिसेप्शन अधिकारी के कैम्पस में बने आवास का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया, घटना की जानकारी तब हुई जब महिला अधिकारी अवकाश से वापस लौटीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद, तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अनुपमा रजक सुपुत्री रामलाल रजक, मूल रूप से बोकारो

झारखंड की रहने वाली हैं और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में निदेशक कार्यालय में रिसेप्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान के कैम्पस में टाईप-२, V / मकान नं २१ रहने के लिए आवंटित किया गया है। अनुपमा ने बताया कि वह बीती २६ अप्रैल से अवकाश पर थीं, बोकारो गई हुई थी। १६ मई को दोपहर बाद जब घर लौटी तो देखा, मेरे घर का मुख्य गेट, एवं अंदर के सभी तीनों दरवाजों के ताले टूटे हुए

थे। जिसकी सूचना तुरन्त संस्थान के सुरक्षा अधिकारी, एवं थाना प्रभारी पीजीआई को दी गई। चोर घर से लगभग ३५-४० हजार रुपए नकद, नौ चांदी के सिक्के, कीमत ७५०० रुपए ०२ जोखी नयी पायल कीमत ८०००/- निकोन का कैमरा, कीमत - ७०००/- नयी ऊलन सूट २ पीस कीमत २५००/- नयी सूती सूट कीमत १५०० पीतल का लोटा (भारी) कीमत ७५०, के अतिरिक्त अन्य कागजात, सर्टिफिकेट गायब हैं।

ग्रिल हटाकर लाखों रुपए की चोरी

लखनऊ। पीजीआई कोतवाली क्षेत्र के साउथ सिटी पुलिस चौकी इलाके में बुधवार रात किसी समय बेखौफ बदमाशों ने खिड़की की ग्रिल हटाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा ले गए, कमरे में सो रहे बुजुर्ग दंपति को घटना की जानकारी नहीं हो सकी, सुबह करीब साढ़े चार बजे जानकारी होने पर ११२ नम्बर पर पुलिस को सूचना दी। बुजुर्ग की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साउथ सिटी के मकान नंबर E-१३६ में कपिल शंकर त्रिवेदी, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। बेटा

नौकरी के कारण बाहर रहता है, बेटा का विवाह हो चुका है। बुधवार शाम करीब साढ़े नौ बजे दोनों ने खाना खाया, और सोने चले गए। सुबह करीब साढ़े चार बजे जब महिला जागी तो देखा पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा है, और लाकर का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब ४ लाख के जेवरात और नकदी चोर चुरा ले गए हैं। घर में चोरी होने की जानकारी होने पर पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंचे, ११२ नम्बर की पुलिस ने पीजीआई कोतवाली पुलिस को सूचना दी, वहां से आए पुलिस कर्मियों ने बुजुर्ग दंपति से कहा, चोरी

गए सामान की लिस्ट लेकर ११ बजे चौकी आइए, चौकी प्रभारी ११ बजे के पहले नहीं आते। रात में खिड़की की ग्रिल काटकर चोरी हो जाने से स्थानीय लोग गुस्से में थे, पुलिस द्वारा बुजुर्ग को चौकी बुलाने की भी बात अच्छी नहीं लगी तो, लोगों ने सरोजनी नगर विधायक डा राजेश्वर सिंह को फोन कर पुलिसिया लापरवाही की जानकारी दी। विधायक के एक्शन के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, फोरेंसिक टीम, और डाग स्क्वाड को बुलाकर जांच पड़ताल की। वहीं पुलिस ने खुलासे के लिए दो दिन का समय मांगा है।

सीबीआई ने आम्रपाली पर २३० करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आम्रपाली लेजर वैली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल शर्मा एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ २३० करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर बैंक अ फ महाराष्ट्र और आंध्रा बैंक के साथ २३० करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। प्राथमिकी के मुताबिक, इन बैंकों ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के टेक जोन-४ इलाके में १.०६ लाख वर्ग मीटर भूखंड पर एक आवासीय भवन विकसित करने के लिए ऋण की मंजूरी दी थी। कंपनी यह कर्ज चुकाने में विफल रही, जिसके बाद ३१ मार्च, २०१७ को उनके खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया था।

बैंक अ फ महाराष्ट्र की शिकायत में आरोप लगाया है कि इस रवैये से बैंक को २३०.६७ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों के एक समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वादा किए गए फ्लैटों की समय पर आपूर्ति नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय में शिकायत की थी। आम्रपाली डेवलपर्स का ४२,००० फ्लैट विकसित करने और बेचने का वादा था। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए फ रेंसिक अडिट का आदेश दिया था। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा १२०-बी (आपराधिक साजिश) एवं धारा ४२० (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

एसपी ग्रामीण ने पैदल गश्त कर अवैध टैक्सि स्टैंड व अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश

लखनऊ। सूबे में अवैध रूप से संचालित किये जा रहे वाहनों और उनके संचालित करने वालों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही करने के मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस ने माल कस्बे में अमल शुरू कर दिया। इसी क्रम में पुलिस कप्तान ने थाने पर बैठक कर कस्बे में पैदल गश्त के दौरान सड़क पर से अतिक्रमण हटवाने के लिये ध्वनि विस्तारक से ब्यपरियों को आगाह कराया। साथ ही कस्बे से संचालित अवैध ईरिक्सा, टैम्पो के चालान कर कब्जे में ले लिया। मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को सूबे में अवैध रूप से चलाये जा रहे ईरिक्सा, टैम्पो और मैजिक सहित डग्गामार वहनो के संचालन पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने और ऐसे स्टैंड संचालकों पर गैंगेस्टर और उनकी सम्पत्ति की जांचकर कुर्क करने की कार्यवाही करने के क्रम में कप्तान के निर्देशन में पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस ने कस्बा वासियों ब्यपरियों

को सड़कों पर अतिक्रमण न करने के लिये ध्वनिविस्तारक से आगाह किया। साथ ही कस्बे से दर्जनों के हिसाब से अवैध रूप से चलाये जा रहे ईरिक्सा, टैम्पो और मैजिक व डग्गामार बसों



को न संचालित करने की चेतावनी दी। वहीं लगभग दर्जन भर ईरिक्सा कब्जे में ले लिया। कस्बे में कप्तान हृदयेश कुमार, माल थाना अध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त कर लोगों को अतिक्रमण प्रति आगाह किया। साथ ही गश्त के दौरान हिस्ट्रीशीटों के सम्बंध में जानकारी ली। शांति व्यवस्था कायम रखने के सम्बंध में लोगों से संवाद किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किये बड़े पैमाने पर जजों व रजिस्ट्रारों के तबादले

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शुक्रवार को प्रदेश के २५१ जजों व रजिस्ट्रार की ट्रांसफर-पोस्टिंग और पदोन्नति की गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश पर डिप्टी रजिस्ट्रार सतीश कुमार पुष्कर की ओर से हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट की ओर से इन सभी जज को तत्काल अपने नवपदस्थापन पर योगदान देने का आदेश दिया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार लखनऊ से कुल ६ जज व रजिस्ट्रार का तबादला किया गया है। इनमें अविनाश सकसेना, जितेंद्र कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह,

राम नगीना यादव, रेखा शर्मा व पद्माकर मणि त्रिपाठी शामिल हैं। वहीं ५ जजों को स्थानांतरित करते हुए लखनऊ में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा ६ जज व रजिस्ट्रार को लखनऊ में ही एक पद से दूसरे पद पर ट्रांसफर किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अब लखनऊ कमर्शियल कोर्ट के प्रिसाइडिंग अफीसर को अब चैयरमैन, कमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल, लखनऊ के नाम से जाना जायेगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

सीएम योगी ने अधिकारियों को ४८ घंटे में सभी अवैध वाहन स्टैंड खत्म करवाने के लिए निर्देश

लखनऊ। प्रदेश सरकार गुरुवार से सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। अवैध वाहन स्टैंड से बुरी तरह नाराज सीएम योगी ने अफसरों को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि अगले ४८ घंटे के अंदर सभी अवैध वाहन स्टैंड खत्म हो जाने चाहिए। हर जगह व्यवस्थित पार्किंग होनी चाहिए, जिससे माफिया, अराजकतत्व और दलाल प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल दूर रहने चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि निधिरित स्थान के बाहर दुकान न लगने देने की हिदायत के साथ

स्पष्ट कर दिया है कि यदि अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या हल न हुई तो इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की



जवाबदेही तय की जाएगी। प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान के लिए इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न संबंधित विभागों को साथ लगाकर

कार्ययोजना बनवाई है। इसकी रूपरेखा उन्होंने बुधवार को लोकभवन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को बताई। सीएम योगी ने कहा कि सड़क और ओवरब्रिज स्टंट करने की जगह नहीं हैं। ऐसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। हेलमेट, सीटबेल्ट के प्रयोग को अनिवार्य रूप से कड़ाई के साथ लागू किया जाए। साथ ही प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनफिट या बिना परमिट के स्कूली बसों का संचालन नहीं होगा।

नवजोत सिंह सिद्धू का आत्मसमर्पण, भेजे गए पटियाला जेल

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जेल भेज दिया गया है। सिद्धू को पटियाला जेल के १० नंबर वार्ड में रखा गया

जिन्होंने इस साल फरवरी में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में आत्मसमर्पण किया था, वह भी पटियाला जेल में बंद है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू को

मच्छरदानी, एक क पी पेन, एक शूज की जोड़ी, दो बेडशीट, चार कुर्ते पजामे और दो सिरहाने का कवर मिला है। सिद्धू को जेल में काम के बदले ३० से ६० रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। सिद्धू के वार्ड से आधा किलोमीटर की दूरी पर बिक्रम जीत सिंह मजीठिया का वार्ड है। दरअसल, सिद्धू को रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। सिद्धू ने कल शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को ३४ साल पुराने रोडरेज मामले में सजा सुनाई है। सिद्धू से जिस व्यक्ति का झगड़ा हुआ था, उसकी मौत हो गई थी।



है। यह वार्ड १२३५ फीट का है। पटियाला जेल में वे कैदी नंबर २४१३८३ बने हैं। सिद्धू के कष्टर प्रतिद्वंद्वी बिक्रम सिंह मजीठिया,

पटियाला जेल में एक कुर्सी, मेज, दो पगड़ी, एक अलमारी, एक कंबल, एक बेड, तीन अंडरवियर और बनियान, दो ट वल, एक

५३ जिलों में १७० मोबाइल यूनिट कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन

लखनऊ। घर पहुंचकर लोगों को एम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले प्रदेश के करीब १००० कर्मचारी दो विभागों के बीच अपने वेतन के भुगतान के लिए जूझ रहे हैं। कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर लगातार नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) व स्वास्थ्य महानिदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लखनऊ समेत प्रदेश के ५३ जिलों में १७० मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) का संचालन हो रहा है। इसका जिम्मा केएचजी हेल्थ सर्विसेज के पास है। प्रत्येक एम्बुलेंस में डक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत पांच स्टाफ मौजूद रहता है। ये एम्बुलेंस गांव में मरीज के घर के पास जाकर इलाज मुहैया कराते हैं। मुफ्त दवाओं का वितरण

करते हैं। खून संबंधी जांचें की जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग से सेवा प्रदाता संस्था को बिल का भुगतान न होने से दूर दराज के ग्रामीण व शहरी इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले कर्मियों को अब तक वेतन नहीं मिल सका है। कंपनी बिल स्वास्थ्य महानिदेशालय भेजती है। महानिदेशालय से बिल एनएचएम जाता है, इसके बाद भुगतान होता है। बिल का भुगतान न होने से स्थिति बदइंतजामी बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों ने कंपनी के अधिकारियों से शिकायत की। इसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान कर्मचारी एनएचएम दफतर गए लेकिन वहां अधिकारियों ने मांग को अनसुना कर दिया है। वेतन भुगतान न होने से कर्मचारी भुखमरी के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने मेडिकल सप्लाय कॉरपोरेशन में मारा छापा, नदारद मिले अफसर

लखनऊ। शुक्रवार को मेडिकल सप्लाय कॉरपोरेशन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सप्लाय कॉरपोरेशन में उन्हें तमाम खामियां मिलीं। वहां बिना किसी सूचना के अफसर भी विभागों से नदारद मिले। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कुछ दिन पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि मेडिकल सप्लाय कॉरपोरेशन को स्पष्ट निर्देश दिए

गए हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खेप पहुंचाई जाए। इसी क्रम में वो शुक्रवार को अचानक



ही मेडिकल सप्लाय कॉरपोरेशन में छापा मारने पहुंचे। जहां उन्हें अपनी जांच में कई विभागों में काफी कमियां देखने को मिली हैं

अद्भुत चाय : नौ करोड़ रुपये किलो की चाय

अमरेन्द्र सहाय अमर बहुत से लोगों को नींद से उठने के बाद चाय की चुस्की चाहिए। ऐसे लोग बिना ब्रश कुल्ला किये चाय पीते हैं जिसे बेड टी कहा जाता है। निश्चित ही चाय दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय है। हम

चाय की पत्तियों के बारे में बताएंगे। यह पढ़ कर आप दंग रह जायेंगे। हम बात कर रहे हैं चीन में मिलने वाली डा-होंग पाओ चाय की। इसे दुनिया की सबसे महंगी चाय का दर्जा मिला हुआ है। इसकी कीमत ६ करोड़ रुपए प्रति

वजह है, जिसके चलते इसको जीवनदायिनी भी कहा जाता है। कई प्रकार की गंभीर बीमारियां इसके सेवन से ठीक होती हैं। खेती के दौरान डा-होंग पाओ की पत्तियों की पैदावार काफी कम मात्रा में होती है और इसकी

की पत्तियों के इतिहास के बारे में एक कहानी प्रचलित है। इसकी खेती की शुरुआत चीन के मींग शासन के समय में शुरू हुई थी। चीनी लोगों का कहना है कि उस दौरान मींग शासन की महारानी अचानक बीमार हो गई थी। उनकी

बाद वह ठीक हो गई। महारानी के ठीक होने के बाद राजा काफी खुश हुए और उन्होंने आदेश दिया कि इस खास तरह की चाय की पत्तियों की खेती की जाए। राजा के लंबे चोंगे के नाम पर ही इस चायपत्ती का नाम



सभी लोगों को चाय पसंद है। दुनिया भर में कई तरह के फ्लेवर्स की चाय मिलती हैं, जिन्हें पीने के बाद स्वाद का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन क्या कभी आपने दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्तियों के बारे में सुना है? आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी

किलोग्राम है। डा-होंग पाओ चायकी खेती चीन के फुजियान के वूईसन इलाके में की जाती है। इस चाय पत्ती के कई सारे लाभकारी गुण हैं, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। स्वास्थ्य के लिए ये चायपत्ती काफी लाभदायक होती है। यही एक बड़ी

पत्तियां दुनिया में काफी दुर्लभ भी हैं। यही एक बड़ा कारण है, जिसके चलते इस चायपत्ती की कीमत ६ करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। इस चाय पत्ती की खेती विशेष तरह से की जाती है, जिसमें मेहनत और ध्यान दोनों लगता है। डा-होंग पाओ चाय

तबीयत काफी बिगड़ गई थी और महारानी के बचने की संभावना काफी कम थी। उन पर किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्हें डा-होंग पाओ चाय पीने के लिए कहा गया। उन्होंने इस चाय का सेवन किया और पीने के कुछ ही दिनों के

डा-होंग पाओ पड़ा। मान्यता है मींग शासन से ही इस चाय पत्ती की खेती होती चली आ रही है। आज कई लोग इस चाय पत्ती के १० से १५ ग्राम खरीदने के लिए लाखों रुपए चुकाते हैं। हालांकि १४ लाख रुपये किलो की चाय भारत में भी बिकती है।

देश में नेतृत्व बदलने से जनता के मन में पैदा हुआ है भरोसा : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश वही है, नेतृत्व बदलने से देश के हर नागरिक के मन में कैसे नया विश्वास जागृत होता है और सरकार कैसे संवेदनशील होकर बिना भेदभाव के योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाने का काम करे ये आज हमें दिख रहा है। राजधानी लखनऊ में शआजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विद्या भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश वही है, नेतृत्व बदलने से देश के हर नागरिक के मन में कैसे नया

विश्वास जागृत होता है और सरकार कैसे संवेदनशील होकर बिना भेदभाव के योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाने



का काम करती है। सीएम योगी ने कहा कि विद्या भारती राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत संस्कारवान पीढ़ी तैयार कर रही है। वहीं, वर्तमान में 'अमृत वर्ष' के अभियान के साथ

जुड़कर अमर बलिदानियों को सम्मान भी दे रही है। हर एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आजादी के 'अमृत काल' को जीवन का ध्येय बनाकर कार्य करे। हमें एक सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण करना होगा, तब भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को १९४७ में आजादी मिली थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने देश के अमर बलिदानियों की परिकल्पना को नजरअंदाज करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया और

देश को धर्म, जाति, साम्प्रदायिक भेदभाव और अलगाववाद की ओर धकेल दिया। वर्तमान में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश संप्रदायवाद, जातिवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद से ऊपर उठकर एकजुट है। आज सरकारें संवेदनशील होकर समाज के प्रत्येक तबके के लिए बिना भेदभाव के कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले वीर सेनानियों की वीर

गाथा को लोगों तक पहुंचाने का जो अभियान शुरू किया गया है, उसके लिए विद्या भारती परिवार को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि विद्या भारती ने १९५२ में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से पक्कीबाग गोरखपुर में एक विद्यालय का शुभारम्भ किया था, लेकिन आज पूरे देश में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संस्कारवान शिक्षा देने का केंद्र बिंदु बन चुका है। विद्या भारती और इससे जुड़ी हुई संस्थाएं वर्तमान पीढ़ी को खड़ा करने का कार्य कर रही है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती राष्ट्रभक्त और संस्कारवान युवा पीढ़ी निर्माण कर रही है।

देओल फैमिली के छोटे चिराग की अब होगी बॉलीवुड में एंट्री

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की एक्टिंग फिल्म इंडस्ट्री में अपान धमाल मचाती रहती हैं। सनी की एक्टिंग के तो उनके फैंस के दिलों में एक जोश ले आती हैं। अब उनके बच्चे भी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। बता दें कि सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल फिल्म 'पल पल दिल के पास' से डेब्यू कर चुके हैं। अब उनके छोटे बेटे राजवीर देओल भी इंडस्ट्री में एंट्री के लिए तैयार हैं। वह राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म से एंट्री करेंगे। राजवीर के साथ इस

फिल्म में पूनम दिल्ली की बेटी पलोमा नजर आने वाली हैं। अब दोनों ही स्टार किड इंडस्ट्री में साथ में धमाल मचाते नजर आने वाले हैं। तरण आदर्श ने ट्वीट करके राजवीर और पलोमा के डेब्यू की जानकारी दी है। बता दें कि इस फिल्म से सूरज बड़जात्या के बेटे अविनाश एस बड़जात्या डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। फिल्हाल इस फिल्म का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। फिल्म की शूटिंग जुलाई २०२२ से शुरू होने

वाली है। फिल्म की कहानी तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर बताया है कि ये फिल्म मर्डन रिलेशनशिप



पर आधारित होने वाली है जो लैविश डेस्टिनेशन वेडिंग के अग्रेस्ट होने वाली है। इस फिल्म को सूरज

बड़जात्या के बेटे अविनाश एस बड़जात्या डायरेक्ट करने वाले हैं। यह उनकी डेब्यू फिल्म होगी। अविनाश ने पलोमा के बारे में कहा कि वह मेरे किरदार के लिए एकदम फिट बैठती हैं। पलोमा और राजवीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत शानदार है और एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों अपने किरदार में एकदम घुल गए हैं। राजवीर और पलोमा की जोड़ी सनी देओल और पूनम दिल्ली की खूबसूरत जोड़ी का शोबैक है।

स्टार एक्टर बोले- हिंदी फिल्मों में साउथ एक्टर बेचते हैं नारियल पानी

मुंबई। इन दिनों बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बीच मामला काफी गर्माया हुआ है और दोनों तरफ के सितारे आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इस बहस के बीच रोज नए-नए बयान सामने आ रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ ने अपने एक

कार्टून बनाया जाता है, जो केवल हंसाने के काम आते हैं। सिद्धार्थ ने महमूद अली का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें लंबे टाइम तक ब लीवुड में कार्टून के करेक्टर में ही दिखाया गया है साथ ही मिथुन चक्रवर्ती का जिक्र करते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि



इंटरव्यू में साउथ इंडस्ट्री को निशाने पर ले लिया है और एक के बाद एक बड़ी बातें कही हैं। इसके पहले साउथ स्टार महेश बाबू के बॉलीवुड के अफोर्ड करने वाले बयान पर लगातार बहस हो रही थी। महेश बाबू ने कह दिया था कि बॉलीवुड उन्हें उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। इससे पहले भी अजय देगवन और किच्चा सुदीप भी ट्विटर पर आपस में उलझ चुके हैं। अब ये बहस इतनी बढ़ गई है कि हर सेलिब्रिटी इस पर कमेंट कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि साउथ के स्टार्स को बॉलीवुड में केवल

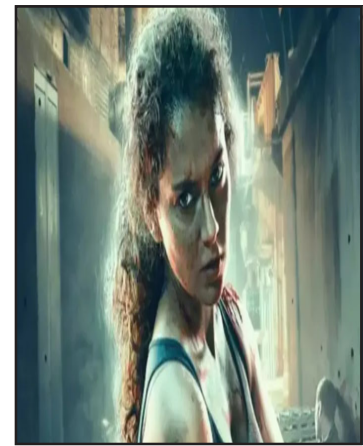
साउथ के एक्टर लंबे समय तक बॉलीवुड में लूगी पहनकर नारियल पानी बेचते रहे हैं। साउथ स्टार महेश बाबू ने बीते दिनों ऐसा कमेंट कर दिया था जिस पर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी पड़ी है। महेश बाबू ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर रिलीज के वक्त कहा था कि ब लीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बात पर बॉलीवुड स्टार्स सहित लोगो ने उन्हें जमकर निशाने पर ले लिया। हालांकि बाद में महेश बाबू ने इस मामले पर सफाई भी दी लेकिन दिनों दिन ये बहस अब और गर्म होती जाती है।

कंगना रनौत की धाकड़ में एक्शन सीन्स भरपूर मगर फिल्म की कहानी दे गई धोखा

मुंबई। कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता स्टारर फिम 'धाकड़' आज रिलीज हो चुकी है। धाकड़ में बैंक टू बैंक एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कहानी के नाम पर फिल्म बेरहमी से ठगती है। एक्शन फिल्म के नाम पर गन्स चलाने और गाड़ियां उड़ाने तक तो ठीक था, लेकिन जब तक पटकथा में दम ना हो, सभी बेकार जाते हैं 'ड्रैगन फ्लाय' नाम की ये स्पेशल एजेंट अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ाने के लिए अकेले ही काफी है। कंगना रनौत के सामने एक नहीं बल्कि छिदो-दो धाकड़ विलेन हैं अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता और इन दोनों ने कंगना के लिए इस फिल्म में काफी मुश्किलें खड़ी की हैं। धाकड़ से अपने डायरेक्शन का डेब्यू कर चुके रजनीश घाई फिल्म की भव्यता व उसके एक्शन में इतने खो गए थे कि कहानी पक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।

फर्स्ट हाफ ही नहीं बल्कि सेकेंड हाफ के काफी समय तक आप कहानी ढूढ़ने में लगे रहते हो।

जबरदस्ती के तूसे गए एक्शन सीक्वेंस कई जगहों पर लॉजिक्स



को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सेकेंड हाफ जितनी उलझी हुई है, उतनी ही सेकेंड हाफ उबाऊ और बोरिंग साबित होती है। पूरे थिएटर में एक ही इमोशन के साथ फिल्म देखते हैं कि भाई कब खत्म होगी?

दिनदहाड़े बंद घर में किया हाथ साफ

लखनऊ। इंदिरानगर थानाक्षेत्र के विमलकुंज निवासी मोहम्मद नजीर ने बताया कि बीते १२ अप्रैल को ईद की खरीदारी करने वह सपरिवार गए थे। वापस लौटने पर उन्हें घर का सारा सामान अस्तव्यस्त मिला। चोरों ने दिनदहाड़े घर के मेनगेट

का ताला तोड़कर १० हजार की नकदी और ज्वैलरी पार कर दी थी। इसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक के आदेश पर इंदिरानगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

lat; cktibz
l hrki g
eks9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
l gsk ukjk; .k feJ
क्षेत्रीय सम्पादक
l kjhk dpekj] fcgkj
eks09386075289
मो० अरशद
C; jks phQ
eऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक,
मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ०प्र० से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566
सम्पादक

आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191.
9026560178
Email-
adbhutsamachar
@yahoo.in
adbhut_samachar
@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक